

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 195/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पॉन्डेन्ट
माधो सिंह पुत्र हरदेवसिंह जाति बावरी निवासी टुंकडा तहसील जैतारण जिला पाली		सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध
आदेश दिनांक 10-6-2016 जो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा
राजस्व अपील संख्या 11/2013 अनवान माधोसिंह बनाम तहसीलदार जैतारण में
पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री ए.के.चौधरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- राजकीय अधिवक्ता रेस्पॉ0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4-10-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम टुंकडा तहसील जैतारण
के खसरा नंबर 216 में 20 बीघा किस्म गै.मु.भाकर भूमि का आवंटन अपीलांट को वन
विकास के लिए आवंटित की गई तथा अपीलांट के पक्ष में किये गये आवंटन के आधार
पर गैर खातेदारी का म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4-8-88 स्वीकृत हुआ । अपीलांट ने
उक्त आवंटित भूमि पर निजी वन विकास हेतु सेकड़ो पोधे लगाये तथा सिंचाई हेतु
ट्यूबवेल व पानी का होद निर्माण करवाया तथा आवंटित भूमि के चारों ओर खाई निर्माण
करवाया तथा आवंटित भूमि को समतल करवाया जिसमें अपीलांट के करीब 4-5 लाख
रुपये खर्च हुए तथा अपीलांट का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा था तथा
अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल करने बाबत राज्य सरकार से कोई नोटिस आदि
प्राप्त नहीं हुआ । परंतु नामांतरकरण संख्या 368 के जरिये अपीलांट के नाम गैर
खातेदारी के रूप में दर्ज भूमि को तहसीलदार जैतारण के आदेश संख्या
राजस्व/90/239 दिनांक 15-3-97 के द्वारा आवंटन निरस्त करने के नोट के आधार
पर उक्त आवंटित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दी । उक्त म्युटेशन संख्या 368 ग्राम
टुंकडा की जानकारी अपीलांट को होने पर उसने उक्त म्युटेशन संख्या 368 के विरुद्ध
अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की जाने पर
अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10-6-2016 के द्वारा उनके समक्ष
प्रस्तुत अपील को खारीज कर दिया जाने पर वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा
के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ता की
बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन
किया कि ग्राम टुंकडा क खसरा नंबर 216 में निजी वन विकास हेतु अपीलांट को 20



DM
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

बीघा किस्म गे0मु0भाकर भूमि विधिक प्रक्रिया अंपनाते हुए उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा आवंटन नियम 12 के तहत आवंटित की । अपीलांट ने उक्त आवंटित भूमि में वृक्षारोपण करवाया, कुआ खुदवाया, भूमि सुधार करवाया तथा उक्त भूमि पर अपीलांट का निरंतर कब्जा चला आ रहा था तथा अपीलांट को उक्त भूमि पर से बेदखल करने बाबत कोई नोटिस आज दिन तक राज्य सरकार की ओर से नहीं दिया गया था । वकील अपीलांट ने अपनी बहस एवं अपीलाधीन भूमि पर कब्जा बाबत दस्तावेजात, फॉटोज आदि इस न्यायालय में दिनांक 24-8-18 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट को आवंटित उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी जिसे नामांतरकरण संख्या 368 के जरिये तहसीलदार जैतारण के आदेश संख्या राजस्व/90/239 दिनांक 15-3-97 के द्वारा आवंटन निरस्त करने के नोट के आधार पर अपीलांट को कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आवंटित भूमि को राजकीय भूमि दर्ज कर दी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अलोटमेंट ऑफ अनकल्चरेबल वेस्ट लेण्ड फोर प्राईवेट फॉरेस्ट नियम 1968 के नियम 18 के तहत आवंटन निरस्तीकरण का अधिकार केवल जिला कलेक्टर को ही है, तहसीलदार जैतारण को कोई अधिकार नहीं होने से उक्त म्युटेशन संख्या 368 के जरिये अपीलांट के खातेदारी को निरस्त करने की जानकारी अपीलांट को होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को विधि के प्रावधानों पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसे निरस्त करने तथा अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार जैतारण ने म्युटेशन संख्या 368 पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उक्त म्युटेशन संख्या 368 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश तथा म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4-8-88 जिसके द्वारा अपीलांट को गैर खातेदार दर्ज किया गया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 368 जिसके द्वारा अपीलांट का नाम तहसीलदार जैतारण के आदेश से हटाते हुए अपीलांट को आवंटित भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज की गई, आदि का अवलोकन किया एवं इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों आदि का भी अवलोकन किया ।

ग्राम टुंकडा तहसील जैतारण के खसरा नंबर 216 में 20 बीघा किस्म गै.मु.भाकर भूमि अपीलांट को वन विकास के लिए वर्ष 1987 में आवंटित की गई तथा अपीलांट के



OM
वकील उभयपक्ष
अधीनस्थ


पक्ष में किये गये आवंटन के आधार पर गैर खातेदारी का म्युटेशन संख्या 347 दिनांक 4-8-88 स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलांत के पक्ष में 25 वर्ष की लीज जारी की गई इसलिए म्युटेशन संख्या 347 अपीलांत के पक्ष में लीजधारी के रूप में स्वीकृत करना था।

निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य बंजर भूमि आवंटन नियमों में शर्तों की पालना नहीं करने तथा लीज अवधि नहीं बढ़ाने पर जिला कलेक्टर को नियम 18 के तहत आवंटन खारीज करने का अधिकार है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा प्रकरण का समुचित परीक्षण कर न्यायिक निर्णय किया है तथा अपीलांत निजी वन विकास हेतु किये गये वृक्षारोपण व विकास कार्यों हेतु लिये ऋण लेने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है तथा यह भूमि कब्जा काश्त के लिए नहीं होकर वन विकास के लिए लीज पर दी थी, जिसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। वन विकास हेतु किये गये खर्चों की पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती है, जो उसे मुआवजे के रूप में दिया जाये।

इसके अलावा अपीलांत द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों की पालना नहीं करने तथा आवंटित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं करने पर अपीलांत के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिये जाने पर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 368 के जरिये भूमि पुनः सिवाय चक दर्ज करने के जो आदेश तहसीलदार जैतारण ने पारित किये, जो विधिसम्मत होने से अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते हैं।

परिणामस्वरूप अपीलांत की उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10-6-2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 4-10-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(मानाराम पटेल)

अतिरिक्त सम्मोचीय अधिकृत
जोधपुर

